

भारतीय जनता पार्टी

लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी द्वारा

गुवाहाटी में संवाददाता सम्मेलन में वक्तव्य

दिनांक 29 सितम्बर, 2008

मैं असम और मेघालय के अपने बहुत ही सन्तोषजनक दो दिन के दौरे के बाद नई दिल्ली लौट रहा हूँ। इस दौरे के दौरान मैंने दो रैलियों को सम्बोधित किया। एक गुवाहाटी में और दूसरी शिलांग में। ये रैलिया मेरी पार्टी द्वारा आयोजित "विजय संकल्प यात्रा" का हिस्सा हैं।

मेरे इस दौरे का मुख्य बिन्दु असम गण परिषद् के नेताओं के साथ हुई मेरी पहली औपचारिक बैठक था। भारतीय जनता पार्टी तथा असम गण परिषद् के बीच प्रस्तावित गठबन्धन असम की राजनीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन में हमेशा हमारा यह मत रहा है कि क्षेत्रीय दलों के साथ भाजपा के संयोजन से न्यायसंगत क्षेत्रीय आकांक्षाओं के साथ राष्ट्रीय दृष्टिकोण में सामंजस्य स्थापित होता है। दोनों के बीच कोई परस्पर विरोध नहीं है। वस्तुतः दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसीलिए असम की जनता के लिए गर्व करना बिल्कुल स्वाभाविक है जब वे हमारे राष्ट्रीय गान "जन गण मन" सुनते हैं और साथ ही वे "ओ मोर आपोनार देश, ओ मोर चिकुनीर देश" भी सुनते हैं जो महान लेखक लक्ष्मीनाथ बेजबरूआ द्वारा लिखित असम का गान है। यह गीत असम की जनता का अपनी मातृभूमि, अपनी विरासत तथा प्राचीन संस्कृति के प्रति स्नेह को बहुत भावनात्मक अभिव्यक्ति प्रदान करता है।

दुःख की बात है कि पड़ोसी देश बंगलादेश से असम में उसके नागरिकों की बे-रोकटोक अवैध घुसपैठ से न केवल असम की परम्पराओं और लोकाचारों को ही बल्कि अब असम के अस्तित्व को भी खतरा पैदा हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आई.एम.डी.टी. एक्ट को असंवैधानिक बताकर खारिज करते हुए बंगलादेशियों की अवैध घुसपैठ को असम तथा भारत के विरुद्ध 'बाह्य आक्रमण' बताया है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने हाल के एक मामले—जिसमें एक पाकिस्तानी नागरिक शामिल था जो पहले बंगलादेश आया और बाद में जिसने असम में अवैध घुसपैठ करके अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करा लिया तथा 1996 में विधानसभा चुनाव लड़ने की भी व्यवस्था कर ली थी—में कटु टीका-टिप्पणी करते हुए चेतावनी दी है कि बंगलादेशी घुसपैठिए असम में 'किंगमेकर' बन गए हैं।

भारतीय जनता पार्टी तथा असम गण परिषद् का मानना है कि यह स्थिति किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश को मानते हुए केन्द्र की भावी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन सरकार असम के अस्तित्व के लिए पैदा हुए इस भयंकर खतरे को समाप्त करने के लिए ठोस कानूनी और प्रशासनिक उपाय करेगी।

वस्तुतः यह हमारा वादा है कि हम यू.पी.ए. सरकार द्वारा असम की जनता से किए गए विश्वासघात के निम्नलिखित कदमों को निष्प्रभावी बनाएंगे।

- अपनी वोट बैंक की राजनीति के चलते बंगलादेश से अवैध घुसपैठियों की बाढ़ को रोकने में **विफलता**।
- ब्रह्मपुत्र नदी में बार-बार आने वाली विनाशकारी बाढ़ को एक प्रभावी दीर्घकालीन नीति के जरिए रोकने में **विफलता**।
- असम की धरोहर और संस्कृति के पावन प्रतीक *माजुली* की सुरक्षा करने में **विफलता**।
- राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, रेल और वायुयान मार्गों का विस्तार और आधुनिकीकरण करने, *आसियान* तथा पड़ोस के अन्य देशों के साथ क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए नए व्यापार मार्ग खोलने जैसी एकीकृत आधारभूत परियोजनाओं के जरिए असम और शेष पूर्वोत्तर क्षेत्र को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा में लाने में **विफलता**।
- उग्रवादी और अलगाववादी ताकतों जिनमें से अधिकांश के लिए बंगलादेश एक सुरक्षित जगह है, को रोकने में **विफलता**।
- असम तथा देश के अन्य राज्यों में प्रत्येक वास्तविक भारतीय नागरिक को बहु-उद्देशीय फोटो पहचान-पत्र जारी करके नागरिकों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करने हेतु एन.डी.ए. सरकार की परियोजना को कार्यान्वित करने में **विफलता**।
- असम के युवाओं के लिए रोजगार तथा उद्यमशीलता के अवसर सृजित करने में **विफलता**।

मैं उपर्युक्त सूची में सभी आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि को रोकने में यू.पी.ए. सरकार की विफलता और आतंकवाद से लड़ने में इसकी विफलता बल्कि अनिच्छा को भी जोड़ना चाहूंगा

असम को बचाना होगा और भारत को यू.पी.ए. सरकार नामक बोझ से मुक्त कराना होगा। यह तभी संभव होगा जब पहले नई दिल्ली में और बाद में अगले विधानसभा चुनाव होने पर गुवाहाटी में अपेक्षित राजनीतिक इच्छा-शक्ति वाली एक राष्ट्रवादी सरकार सत्ता में

आए। इसलिए असम की जनता से मेरी यह अपील है कि “असम से भारतीय जनता पार्टी और असम गण परिषद् के ज्यादा से ज्यादा संख्या में सांसद भेजें और केन्द्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन (एन.डी.ए.) की सरकार बनाने में हमारी मदद करें।”

आज शिलांग के दौरे के दौरान मेरी हिन्दुओं, मुसलमानों और ईसाइयों सहित विभिन्न धर्मों के धार्मिक नेताओं के साथ बहुत ही लाभप्रद बैठक हुई है। मुझे उन घटनाओं जैसे निर्दोष ईसाइयों की हत्या और कुछ चर्चों पर हुए हमलों पर टिप्पणी करने का भी मौका मिला जो हाल में उड़ीसा तथा कर्नाटक के कुछ हिस्सों में घटी हैं। मैं हिंसा और बर्बरता के इन कृत्यों की कड़े शब्दों में निन्दा करता हूँ जिनको माफ नहीं किया जा सकता अथवा औचित्यपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता। कानून अपना काम करे और दोषियों को इसकी सजा मिले।

मैंने इस बैठक में इस बात पर भी बल दिया कि ऐसे सभी मुद्दों जिनसे किसी भी समुदाय के मन में उत्तेजना पैदा होती हो, पर विभिन्न धर्मों के बीच खुली और रचनात्मक बातचीत होनी चाहिए। सभी धार्मिक समुदायों के लोग सचेत होकर भारतीयता जो हम सभी को एक साथ बड़े राष्ट्रीय समुदाय में जोड़ती है, के बन्धनों को मजबूत बनायें।
